



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 14 जून, 2004/24 ज्येष्ठ, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 जून, 2004

संख्या वित्त-आई० एफ०(सी एच) 5-3/93-II.—हि० प्र० निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण अधिनियम, 1999 (2000 का 19) की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार प्रारूप नियम नामतः दी हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण नियम, 2004 समसंख्यांक अधिसूचना तारीख 16 फरवरी, 2004 द्वारा राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में दिनांक 2 मार्च, 2004 को इससे संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से इनके प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करने के लिए, प्रकाशित किए गए थे। और इस प्रकार इन नियमों पर किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से किसी भी प्रकार का आक्षेप और सुझाव उपरोक्त निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण अधिनियम, 1999 (2000 का 19) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

नियम

संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण नियम, 2004 है।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण अधिनियम, 2000 (2000 का 19) अभिप्रेत है।

(ख) उन सभी शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. सक्षम प्राधिकारी का अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने का अधिकार.—सक्षम प्राधिकारी को किसी वित्तीय स्थापन या इसके अधिकारियों या सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति से वित्तीय स्थापन के बारे में ऐसी सूचना जैसी अपेक्षित हो के बारे पूछने की शक्ति होगी।

4. अतिरिक्त संपत्ति अभिकरण करने की शक्ति.—(1) जहां सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है या विश्वास करने का कारण है कि किसी वित्तीय स्थापन ने संपत्ति या धन छिपाया है जो अधिनियम के अधीन कुर्क किए जाने के लिए दायी है, तो वे ऐसी संपत्ति के अभिग्रहण करने का आदेश करके कि ऐसे धन या संपत्ति को सरकार या प्राधिकृत अधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा के बिना अन्तरित या अन्यथा व्यय न किया जाए का आदेश कर सकेगा और मामले को अधिनियम की धारा 3 के अधीन अन्तरिम कुर्की का आदेश जारी करने के लिए तुरन्त सरकार या प्राधिकृत अधिकारी को निर्दिष्ट करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी उप-नियम (1) के अधीन जिस संपत्ति के बारे में अभिग्रहण का आदेश किया गया है का कब्जा लेने के लिए सरकार के किसी अधिकारी की सहायता ले सकेगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी, द्वारा जब भी अपेक्षा की जाए तो किसी पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, संपत्तियों की खोज और पहचान करने के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति, स्थान, संपत्ति, दस्तावेजों, लेखे की पुस्तकों इत्यादि के बारे में जांच अन्वेषण तथा सर्वेक्षण सहित सभी प्रकार के कदम उठाएगा।

5. सक्षम प्राधिकारी के नियन्त्रणाधीन अन्तरित संपत्ति या धन का अनुरक्षण.—सक्षम प्राधिकारी इसे अन्तरिम की गई संपत्ति या धन के अनुरक्षण और बनाए रखने के लिए सभी युक्तियुक्त सावधानी बरतेगा और प्राप्त की गई, प्रगन्ध की गई और निपटान की गई संपत्ति और धन के बारे में सभी प्रकार की प्राप्त की गई आय और उपगत व्यय का अभिलेख बनाएगा और उसे विशेष न्यायालय को प्रस्तुत करेगा।

6. सक्षम प्राधिकारी विशेष लोक अभियोजक की सहायता करना.—सक्षम प्राधिकारी, विशेष न्यायालय में मामलों का संचालन करने में विशेष लोक अभियोजक की ऐसी सहायता करेगा जैसी अपेक्षित हो।

आदेशानुसार,

एस0 एस0 परमार,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त)।

[Authoritative English text of this department notification No. Fin-IF(Ch)5-3/93-II dated 4-6-2004 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th June, 2004

No. Fin-IF(Ch)-5-3/93-II.—Whereas the draft the Himachal Pradesh Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishment) Rules, 2004 were published, as required under sub-section (1) of section 15 of the Himachal Pradesh Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishment) Act, 1999 (Act No. 19 of 2000), in the Himachal Pradesh Rajpatra (Extraordinary) dated 2nd March, 2004 *vide* this Department notification of even number, dated 16th February, 2004 for inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected by these Rules within a period of thirty days from the date of their publication.

And whereas, no objection or suggestions have been received from any person or persons within the above stipulated period.

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the said Act, is pleased to make the following rules, namely:—

RULES

1. *Short title.*—These rules may be called the Himachal Pradesh Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishments) Rules, 2004.

2. *Definitions.*—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Himachal Pradesh Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishment) Act, 1999 (Act No. 19 of 2000).

(b) All words and expression used herein and not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. *The Competent Authority's right to procure additional information.*—The Competent Authority shall have the power to ask any Financial Establishment or its officers or authorised officer of the Government or a local authority or any other person to furnish such information as may be required in relation to Financial Establishment.

4. *Powers to seize additional property.*—(1) Where the Competent Authority is satisfied or has reasons to believe that any Financial Establishment has concealed the property or money which is liable to be attached under the Act, it may order the seizure of such property by ordering that such money or property shall not be transferred or otherwise dealt with except with the prior permission of the Government or authorised officer and shall refer the matter forthwith to the Government or authorized officer for issuing the *ad-interim* attachment order under section 3 of the Act.

(2) The Competent Authority may take the assistance of any Officer of the Government to take possession of the property in respect of which an order of seizure has been made under sub-rule (1).

(3) Any officer in charge of Police Station when required by the Competent Authority, shall take all steps, including enquiry, investigation or survey in respect of any persons, place, property, documents, books of account etc. for the purpose of tracing and identifying the properties.

5. *Upkeep the property or money transferred under the control of Competent Authority.*—The Competent Authority shall take all reasonable care for the upkeep and maintenance of the property or money transferred to it and maintain a record of all income received and expenditure incurred in respect of the property or money received, managed, and disposed of and furnish the same to the Special Court.

6. *Competent Authority to assist Special Public Prosecutor.*—The Competent Authority shall render all such assistance to the Special Public Prosecutor in conducting the cases in the Special Court, as may be required.

By order,

S. S. PARMAR,
Addl. Chief Secretary (Finance).